

केंद्र ने PMGAY के तहत आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र ने [प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना](#) के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराने के उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल्याणकारी पहल के तहत ये घर आत्मसमर्पण करने वाले [नक्सलियों और नक्सल हिसा](#) से प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित किये जाएंगे।

- इस बात पर जोर दिया गया कि इस योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 सूचियों से बाहर रह गए परिवारों को शामिल करना है।

मुख्य बंदि

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- **परिचय:**
 - वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना है।
 - लाभार्थियों के चयन में तीन चरणों की गहन सत्यापन प्रक्रिया शामिल है, जिसमें [सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011](#), [ग्राम सभा अनुमोदन](#) और [जियो-टैगिंग](#) शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुँचे।

PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को मलिया:

- **वित्तीय सहायता:** मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
- **शौचालयों के लिये अतिरिक्त सहायता:** [सबसे गरीब भारत मशिन - ग्रामीण \(SBM-G\)](#) या [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
- **रोजगार सहायता:** आवास निर्माण के लिये [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम \(MGNREGA\)](#) के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मजदूरी रोजगार का अनिवार्य प्रावधान।
- **बुनियादी सुविधाएँ:** प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से जल, [तरलीकृत पेट्रोलियम गैस \(LPG\)](#) और वदियुत कनेक्शन तक पहुँच।

नक्सलवाद

- इसकी **शुरुआत स्थानीय जमींदारों के वरिद्ध वदिरोध के रूप में हुई**, जनिहोंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पटिाई की थी।
 - यह वदिरोध 1967 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य कानून सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों के बीच भूमिका उचित पुनर्वितरण करना था।
- **पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ** यह आंदोलन पूरवी भारत के अन्य कम विकसित क्षेत्रों जैसे **छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैल चुका** है।
- ऐसा माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और वचिरधारा का समर्थन करते हैं।
 - **माओवाद माओ त्से तुंग** द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है।
 - यह सशस्त्र वदिरोध, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का सदिधांत है।

वामपंथी उग्रवाद

परिचय

- उत्पत्ति: वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में विद्रोह
- उद्देश्य: क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव

विचारधारा

- सशस्त्र क्रांति (हिंसा और गुरिल्ला पद्धति) के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध
- माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना

ज़िम्मेदार कारक

- विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों के कारण **जनजातीय आबादी का वृहद स्तरीय विस्थापन**
- आदिवासी असंतोष**; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 जनजातियों को वन संसाधनों की कटाई करने से रोकता है
- निर्धनता और स्थायी साधनों की कमी**; नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिये प्रेरक कारक
- प्रभावी शासन का अभाव**; नक्सलवाद के विरुद्ध अपर्याप्त तकनीकी खुफिया जानकारी

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य

- रेड कॉरिडोर**: गंभीर नक्सलवाद-माओवादी विद्रोह का अनुभव
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल

वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने हेतु सरकारी पहलें

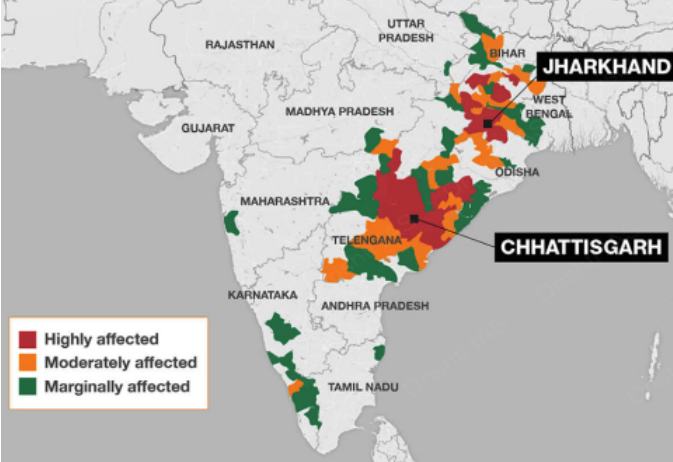
- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015
- SAMADHAN सिद्धांत
 - S- स्मार्ट लीडरशिप
 - A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
 - M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
 - A- एकशनेबल इंटेलिजेंस
 - D- डैशबोर्ड-बेस्ड KPIs (Key Performance Indicators) और KRAs (Key Result Areas)
- H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी
- A- एकशन प्लान फॉर इच थिएटर
- N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
- सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)
- ऑपरेशन ग्रीन हंट
- ग्रेहाउंड** (आंध्र प्रदेश का इलीट कमांडो फॉर्स)
- बस्तरिया बटालियन** (छत्तीसगढ़ में स्थानीय नियुक्तियाँ जो भाषा और इलाके से परिचित हैं, जिससे खुफिया जानकारी एकत्रित की जा सके और ऑपरेशन किये जा सकें)

नक्सलवाद का सामना- बंदोपाध्याय समिति (वर्ष 2006)

- इसमें जनजातियों के प्रति आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव एवं शासन की अपर्याप्त नीतियों पर प्रकाश डाला गया
- इसमें आदिवासियों के लिये भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की सिफारिश की गई

A map of India's Maoist conflict

A crackdown on Maoist rebels has led to a rise in the number of casualties in the country's tribal areas. Here are the regions that are most affected.



Drishti IAS

